



**पृष्ठ 4**  
**लगातार लैपटॉप या मोबाइल पर काम करते हैं तो आंखों को यूँ दें आराम**



**पृष्ठ 5**  
**'धाकड़' के लिए अर्जुन रामपाल ने करवाया अपना मेकओवर**



- देहरादून
- वर्ष 28
- अंक 151
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00

**आज का विचार**

अत्याचार और अनाचार को सिर झुकाकर वे ही सहन करते हैं जिनमें नैतिकता और चरित्र का अभाव होता है।  
— कमलापति त्रिपाठी

# दून वैली मेल

29 वां वर्ष

**सांध्य दैनिक**

email: doonvalley\_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डिजिटल से मान्यता प्राप्त

## पद संभालते ही एक्शन में आये सीएम मुख्य सचिव सहित तमाम बड़े अधिकारी किए जाएंगे इधर-उधर



संवाददाता

देहरादून। राज्य के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पदभार ग्रहण करते ही फुल एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के चंद घंटे बाद ही कैबिनेट की बैठक बुलाने और मुख्य सचिव को स्थानांतरित किए जाने के साथ राज्य के बड़े अधिकारियों को इधर-उधर करने

की खबरों के बीच आज कोरोना पीड़ित पंद्रह सौ परिवारों के लिए राशन से लदे वाहनों को पहाड़ों पर खाना कर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वह कितनी तेजी से और किस तरह काम करने वाले हैं।

बीते कल शाम पद संभालते ही उनके द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाकर

उन्होंने प्रदेश में खाली पड़े 22 हजार पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान को मंजूरी और उपनल कर्मियों के सामान काम और सामान वेतन के मसले की तरफ कदम बढ़ा दिया था। लोगों ने

**सुखवीर सिंह संधू होंगे नए मुख्य सचिव**  
**राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा: धामी**

सोचा भी नहीं होगा कि वह मुख्य सचिव से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों को इधर-उधर कर सकते हैं। लेकिन सुबह ही खबर आई कि मुख्य सचिव ओमप्रकाश को उनके पद से हटाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर एनएचएआई में चेरमैन पद पर तैनात

शेष पृष्ठ 3 पर

## राज्य में 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल

नगर संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही घट रहे हों लेकिन प्रदेश सरकार फिलहाल कोविड कर्फ्यू खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं है। कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह तक और बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू की अवधि छह जुलाई की सुबह छह बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह छह बजे तक होगी। कोविड कर्फ्यू में बाजार पूर्व की भांति साप्ताहिक बंदी के दिन ही बंद रहेंगे।

जानकारी के अनुसार सरकार ने पूर्व में लागू

रियायत को बरकरार रखने के साथ ही शॉपिंग माल खोलने की छूट दी गई है। विदित हो कि प्रदेश में 10 मई को एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसके बाद कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कर्फ्यू को एक-एक हफ्ते के लिए निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में सप्ताह में छह दिन बाजार सुबह आठ से शाम सात बजे तक खुल रहे हैं। आवश्यक सेवाओं के कार्यालय सौ फीसद और शेष कार्यालय 50 फीसद क्षमता के साथ खुल रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को कोचिंग देने वाले संस्थानों को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है। चिड़ियाघर, पार्क भी खोल दिए गए हैं। जिम भी 50 फीसद क्षमता के साथ खुले हैं।

कर्फ्यू में मिल रही छूट के बीच ही शॉपिंग माल संचालकों द्वारा मॉल खोलने की मांग की जा रही थी। सरकार ने शॉपिंग मॉल्स को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, आडिटोरियम को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं दी है।



## गोमती रिवर फ्रंट घोटाला: सीबीआई ने यूपी, बंगाल व राजस्थान के 40 से अधिक जगहों पर की छापेमारी

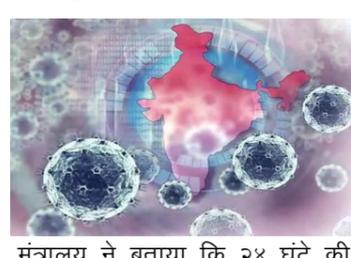
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी सरकार के समय उत्तर प्रदेश के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने सोमवार नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी ने इस मामले में गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा सहित 43 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी अभियान किया है। उन्होंने बताया कि सुबह तड़के शुरू हुआ अभियान अब भी जारी है और दिन में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार के इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों सहित लगभग 920 लोगों को दर्ज एफआईआर में आरोपी बताया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा परियोजना से संबंधित यह दूसरी एफआईआर है। यह उत्तरप्रदेश की अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 9,500 करोड़ रुपए से गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने की इस योजना में अनियमितता की जांच के आदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद दी गई थी। बता दें कि राज्य में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी से मायावती, कांग्रेस, अन्य लोगों के बीच, राज्य को भाजपा से छीनने की कोशिश की जा रही है।



## देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 39 हजार से अधिक मामले दर्ज, रिकवरी रेट 97.11 प्रतिशत

नई दिल्ली। देश में जानलेवा कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव अब कम हो गया है। इसके मद्देनजर देश के कई राज्यों में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी जा रही है। हालांकि अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह आठ बजे तक अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या और घटकर 8,22,099 हो गई है और यह कुल संक्रमण का 9.52 प्रतिशत है जबकि कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 99.99 प्रतिशत हो गई है।



मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे की अवधि में उपचाराधीन मामलों की संख्या 3,296 घटी है। आंकड़ों के मुताबिक, रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए कुल 92,22,508 जांच की गई जिसके बाद देश भर में कोविड-19 के लिए की गई जांचों का कुल आंकड़ा 89,89,99,849 हो गया है।

दैनिक संक्रमण दर 2.69 प्रतिशत दर्ज की गई। लगातार 22 दिनों से यह दर पांच प्रतिशत से कम बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक साप्ताहिक संक्रमण दर भी घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई है।

मंत्रालय ने बताया कि लगातार 53 दिनों से स्वस्थ होने वालों की संख्या रोजाना सामने आ रहे मामलों से ज्यादा बनी हुई है। साथ ही इसने बताया कि बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,89,00,830 हो गई है।

मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोविड-19 रोधी टीके की कुल 35.22 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।

## दून वैली मेल

### संपादकीय

#### क्या गुल खिलाएगा नेतृत्व परिवर्तन?

चार महीने से भी कम समय में दो बार मुख्यमंत्री बदलने वाले भाजपा और उसके नेता भले ही इसके पीछे संवैधानिक संकट का हवाला देकर सत्य को छिपाने का प्रयास कर रहे हो लेकिन आम आदमी इसके पीछे छुपे कारणों को समझ रहा है। इस तरह के परिवर्तनों के पीछे भले ही भाजपा अच्छे परिणामों की उम्मीद लगाए बैठी हो लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। चार साल के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह को जब कुर्सी से हटाया गया तो उनके हर बयान से असंतोष और बगावत झलकती देखी गई। तीरथ रावत को सीएम पद से हटाए जाने की जो खुशी उनके चेहरे पर दिखी वह नए सीएम बने पुष्कर धामी से भी कहीं अधिक थी। शायद उन्हें ऐसा लगा कि बीसी खंडूरी की तरह पार्टी फिर उन्हें ही दोबारा सीएम बना सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण जो भी रहा हो लेकिन स्वयं को बलि का बकरा बनाए जाने से तीरथ रावत भी खुश नहीं है। भले ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण से पहले सूबे के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दबाने में सफलता हासिल कर ली हो लेकिन जिन नेताओं को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था उनकी नाराजगी अभी भी बरकरार है। भले ही कल उन्होंने धामी के साथ मंत्री पद की शपथ ले ली हो। ऐन चुनाव पूर्व किए गए इन परिवर्तनों से प्रदेश भाजपा के नेताओं के बीच भारी असंतोष भर दिया है असंतोष की यह चिंगारी कब शोला बन जाए इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। पुष्कर धामी जिन्हें काम करने के लिए मात्र चार-पांच महीने का समय मिला है वह क्या काम कर पाएंगे सिर्फ यही सवाल नहीं है उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वह अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैसे एक सूत्र में बांधे रख पाते हैं? राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा सौंप कर क्या वह उनके असंतोष को कम कर पाएंगे? ऐसा संभव नहीं दिखता है। क्योंकि कुछ बड़े और अनुभवी नेताओं को कम उम्र व अनुभव वाले पुष्कर धामी की लीडरशिप कतई नहीं पच पा रही है। यह अलग बात है कि वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा भीतर घात की शिकार नहीं होगी इसकी संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। धामी के युवा चेहरे पर दांव खेलकर भाजपा ने राज्य के युवाओं को खासकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को जरूर एक संदेश दिया है कि भाजपा में उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन सूबे के युवाओं को अपने साथ लाने के लिए युवा सीएम को भी उनके लिए इन 4 माह में बहुत कुछ करना होगा। जहां तक आम जनमानस की बात है कि वह भाजपा द्वारा इस चेहरे बदले जाने पर क्या सोचता है? दो दिनों में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले मैसेज यह बताने के लिए काफी है। 2022 के चुनावी लाभ के लिए किए गए इस नेतृत्व परिवर्तन से भाजपा को क्या मिल पाता है इसका फैसला चुनाव परिणाम ही करेगा।

#### लहर-कहर के बाद सेहत के जायके

विनय मोघे

कोरोना ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। हमारे रहन-सहन और खानपान में बहुत बदलाव आया है। हर लहर के साथ हम बदलते जा रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में और क्या-क्या देखने को मिल सकता है। आइये, देखते हैं एक झलक। चाय की दुकान की तरह हर नुकड़ पर काढ़े की दुकानें दिखेंगी। जैसे सुपर ए-वन काढ़ा सेंटर। इन दुकानों पर विभिन्न प्रकार का काढ़ा मिलेगा जैसे सादा काढ़ा, स्पेशल काढ़ा, फुल काढ़ा, हाफ काढ़ा, डबल काली मिर्च वाला काढ़ा। मशीन की चाय और कॉफी की तरह मशीन का काढ़ा भी होगा। पर लोगों को मशीन के काढ़े की जगह उबला हुआ देशी काढ़ा ही पसंद आएगा जैसे कि उबली हुई चाय पसंद आती है। इन दुकानों पर हल्दी वाला दूध भी मिलेगा। ज्यादा हल्दी वाले दूध को डबल हल्दी वाला दूध कहा जायेगा। फलों के जूस की दुकानों पर गिलोय का जूस भी मिलेगा। प्याऊ की तरह बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के अन्य जगहों पर भाप लेने की मशीन लगी होगी। इन मशीनों पर लिखा होगा फलों के स्मरण में भाप की मशीन लगाई गई है। सुलभ शौचालय की तरह स-शुल्क भाप की मशीन भी स्थापित होंगी। जो लोग शुल्क अफोर्ड कर सकेंगे वे इन भाप मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। चाट में भी कचोरी-समोसे में भी तीखी खट्टी-मीठी चटनी के साथ गिलोय की चटनी भी दी जाएगी। पोहे के ऊपर जीरावन की तरह कालीमिर्च का पाउडर छिड़का जायेगा। पानी-पतासे में एक फ्लेवर और बढ़ जायेगा, गिलोय के पानी वाले पानी पतासे। आखिर में हल्दी वाला पतासा भी खिलाया जायेगा। मीठे में गिलोय की रबड़ी, गिलोय के गुलाब जामुन, गिलोय की बर्फी मिलेगी। पिज्जा के ऊपर टॉपिंग में काली मिर्च और गिलोय की टॉपिंग होगी। यदि कोई ग्राहक चाहे तो गिलोय या काली मिर्च की एक्सट्रा टॉपिंग करा सकेगा। पिज्जा की तरह अन्य जंक फूड भी गिलोय और कालीमिर्च युक्त रहेंगे। घर के खाने में भी गिलोय, काली मिर्च, हल्दी का बहुतायत में प्रयोग किया जायेगा। रोज के खाने में सलाद के साथ गिलोय के पापड़ और गिलोय का आचार खाया जायेगा। घरेलू रेसिपी में भी गिलोय और काली मिर्च की विभिन्न डिश बनाई जा सकेगी जैसे स्टीम गिलोय बॉल्स विद हल्दी, गिलोय का शाही परांठा, काली मिर्च की गुजिया आदि। जब आप होटल में खाना खाने जायेंगे तो हो सकता है कि आपको वहां मेन्यू कुछ इस तरह का मिले फ्रेश गिलोय लाइम, क्रीम ऑफ गिलोय सूप, गिलोय लॉलीपॉप, गिलोय क्रिस्पी, कालीमिर्च 65, गिलोय मसाला, गिलोय फ्राई, कढ़ाई गिलोय, गिलोय

## युवाओं को शासकीय रोजगार देने का संकल्प

नगर संवाददाता  
देहरादून। नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए शासकीय रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।

कैबिनेट के 06 संकल्प और 07 निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट ने संकल्प लिया है कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प है। सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है, इससे जहाँ एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।

बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है। आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस



को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है। विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार

### नई सरकार ने कैबिनेट में लिए 6 संकल्प कैबिनेट ने सात फैसलों पर लगाई मुहर

संकल्पित है। दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन को सरकार संकल्पित।

शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने सात प्रमुख निर्णय भी लिये हैं जिनके अनुसार अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ा कर 25 हजार किया जाएगा। मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर वाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों

को रिक्त नहीं समझा जायेगा। राजकीय पॉलिटैक्निक में कई सालों से संविदा कर्मियों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा।

मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके सदस्य डॉ धन सिंह रावत और रेखा आर्य होंगे। जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। जनपद के नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।

बताया कि विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य गणेश जोशी और डॉ धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।

## कांग्रेस में भाजपा से ज्यादा उथल-पुथल रावत समर्थक प्रीतम खेमे का सोशल मीडिया में उड़ा रहे मखौल

नगर संवाददाता  
देहरादून। उत्तराखण्ड में राजनीति में पिछले कुछ दिनों में जो उलटफेर हुआ है उससे प्रदेश की जनता भी हैरान है कि आखिर यह क्या हो रहा है। इधर भाजपा ने सीएम बदल दिया उधर कांग्रेस पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। कांग्रेस नेता दिल्ली दरबार में ही जमे हुए हैं और यहाँ प्रदेश का मुखिया ही बदल गया। बात यहीं नहीं रूकती, बल्कि जो कांग्रेस आज नेतृत्व परिवर्तन पर



बयानबाजी कर रही है उसमें ही अंदरूनी उठापटक इस कदर चल रही है कि नेताओं के समर्थक दूसरे नेता को कोष रहे हैं।

उत्तराखण्ड की राजनीति में भले ही आम जनता बहुत ज्यादा रूचि न रखती हो लेकिन इन दिनों चल रहे घटनाक्रम ने जनता का ध्यान भी खींचा है। अब प्रदेश का निजाम बदल गया है लेकिन शांति तो फिलहाल भाजपा में भी नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस में भी एक हफ्ते से ज्यादा समय से माहौल गरमाया हुआ है। प्रदेश नेतृत्व और पूर्व सीएम के बीच अकसर तलवार खिंची रहती है और इन दिनों यह मतभेद समर्थकों के जरिए भी झलक रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत पिछले लंबे समय से आगामी चुनाव के लिए चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जबकि चेहरे पर चुनाव लड़ने से प्रदेश नेतृत्व के साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्व. डा. इंदिरा हृदयेश सहमत नहीं थे।

डा. इंदिरा के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर भी जो बखेड़ा चल रहा है वह अब तक नहीं

निपटा है। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत सोशल प्लेटफार्म पर खासे सक्रिय हो गये हैं। वहीं उनके समर्थक भी सोशल प्लेटफार्म के जरिए रावत विरोधियों को जम कर कोस रहे हैं। एक तरह से इन समर्थकों ने पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव के लिए चेहरा बनाये जाने को मुहिम चला रखी है और विरोधी गुट के खिलाफ कैसी भी टिप्पणी करने में पीछे नहीं हट रहे हैं।

इस तरह से यह साफ हो रहा है कि भाजपा को कोसने वाले कांग्रेसी अब खुद के नेताओं को ही कोस रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है और भाजपा ने यहाँ का मुखिया ही बदल दिया। ऐसे में कांग्रेस को भी सबक लेते हुए आगामी चुनाव के लिए मैदान में उतरना होगा लेकिन अगर इसी तरह से दिल्ली में इनके दिन कटते रहे और आपस में इसी तरह से सोशल प्लेटफार्म के जरिए बयानबाजी और एक दूसरे को कोसने का सिलसिला जारी रहेगा तो कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझ कर रह जाएंगे।

इन्द्रस्य सख्यमृभवः  
समानशुर्मनोर्नपातो अपसो दधन्विर।  
सौधन्वनासो अमृतत्वमेरिरे विष्ट्वी  
शमीभिः सुकृतः सुकृत्यया ।।

(ऋग्वेद ३-६०-३)

ज्ञानी मनुष्य प्रभु की मित्रता को प्राप्त करते हैं। वे ज्ञानपूर्वक कर्म करते हैं और सदैव प्रभु का स्मरण करते हैं। ऐसे मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं।

Knowledgeable humans attain the friendship of God. They do deeds knowledgeably and always remember the God. Only such humans are entitled to attain the salvation.

(Rig Veda 3-60-3)

## सुको ने आईटी एक्ट 66ए के असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी हो रही एफआईआर पर जताई हैरानी

नई दिल्ली। आईटी एक्ट 66ए को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद इसके तहत थानों में एफआईआर दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जाहिर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने पीयूसीएल की अर्जी पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पीयूसीएल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 2019 में आईटी एक्ट की 66ए को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद थानों ट्रायल कोर्ट में इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र देश भर में सभी थानों में इसके तहत एफआईआर दर्ज न करने के लिए एडवाइजरी जारी करे। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र इस सेक्शन के तहत पुलिस स्टेशनों में पेंडिंग एफआईआर/ जांच कोर्ट में चल रहे मुकदमों का डेटा उपलब्ध कराए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये हैरान परेशान करने वाला है कि साल 2019 में इस धारा को सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है। आपको बता दें कि इसके पहले नवंबर 2020 में यूपी पुलिस को साल 2019 के श्रेया सिंघल के मामले को लेकर बार-बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी लेकिन यूपी पुलिस तब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अनभिज्ञा दिखाई दे रही थी। जबकि इस फैसले के तहत आईटी एक्ट की धारा 66ए को असंवैधानिक करार दिया जा चुका था। नवंबर 2020 में ही इस मामले के पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 66ए के तहत पिछले साल दर्ज की गई एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया था।

## पीएम मोदी ने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का लिया हालचाल

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबियत रविवार शाम को अचानक अधिक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के इन्सिडेंट में भर्ती कराया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को फोन किया और उनके पिता का हालचाल पूछा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सीएम योगी को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम को सर्वोत्तम मेडिकल सुविधाओं के साथ बेहतर इलाज दिया जाए। आपको बता दें कि खुद योगी आदित्यनाथ रविवार को ही कल्याण सिंह को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए थे। योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों को कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर पूरी सतर्कता बरतने को कहा और उनके ट्रीटमेंट में हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि वो लगातार उन्हें पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते रहें।

## बंदर पकड़ने को चलाया अभियान

रुद्रप्रयाग (आरएनएस)। नगर में प्रशासन द्वारा बंदरो को पकड़ने का अभियान चलाया गया। तहसील प्रशासन व वन विभाग के संयुक्त नेतृत्व में मंदिर मार्ग पर पिंजरा लगाकर बंदरों को पकड़ा गया। ऊखीमठ नगर में बंदर लगातार राहगीरों पर हमले कर रहे हैं। पिछले एक महीने में डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोगों को काट चुके हैं। बंदरों के खोफ इस प्रकार है कि बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं घरों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। रविवार सुबह साढ़े छह बजे से प्रशासन की टीम बंदरों को पकड़ने में जुटी रही। बंदरों को पकड़ने में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो पाई दिनभर कड़ी मशक्कत के बाद पांच बंदर ही पकड़े गए। वहीं दूसरी ओर बन्दर और आक्रामक हो गए हैं रविवार को राइका ऊखीमठ में वैक्सीन लगाने जा रही महिलाओं को बंदरों ने भगाया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष विजय राणा, एसडीएम जितेंद्र वर्मा, नायब तहसीलदार जेआर बधाणी, कानूनगो जयकृत सिंह रावत, सभासद प्रदीप सिंह, रविन्द्र सिंह, वन दरोगा कुंवर लाल, सतीश भट्ट, दिवाकर डिमरी, आशीष राणा आदि थे।

## मुख्य सचिव सहित तमाम बड़े अधिकारी किये... >>> पृष्ठ 1 का शेष

सुखवीर सिंह संधू को ओमप्रकाश की जगह मुख्य सचिव पद पर लाया जा रहा है। भले ही अभी इसका सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है लेकिन मिली जानकारी के अनुसार बहुत जल्द सुखवीर सिंह संधू देहरादून पहुंचने वाले हैं। संधू प्रधानमंत्री मोदी के निकट निकटस्थ माने जाते हैं तथा 1988 बैच के तेजतर्रार अधिकारी हैं। खबर यह भी है कि सचिवालय के ही नहीं कई जिलों के अधिकारियों को भी जल्द बदला जाएगा।

उधर राज्य के कोरोना प्रभावितों की मदद के लिए भी सरकार तेजी से काम करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री धामी ने आज राज्य के पंद्रह सौ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए राशन किट लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। उनकी सरकार कोरोना प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी तथा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के पुख्ता इंतजाम की तैयारियां की जाएगी।

## ईट भट्टा मालिक हत्याकांड दो गिरफ्तार, सात पर मुकदमा दर्ज



हमारे संवाददाता मंगलौर/देहरादून। ईट भट्टा मालिक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दो तमंचे व कारतूस भी बरामद किये हैं। मामले में सात अन्य लोग भी षड्यंत्र रचने के आरोपी बनाए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

एसएसपी हरिद्वार डी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया 29 जून को कुमराड़ा में बदमाशों द्वारा ईट भट्टा स्वामी अजय मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले के खुलासे के जुटी पुलिस टीम ने बीते रोज दोनों शूटरों विपिन पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम सरोला माजरा, अभिषेक पुत्र अशोक निवासी

बहेड़ी गुज्जर को मोहम्मदपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दो तमंचे व कारतूस भी बरामद कर लिये।

पूछताछ में पता लगा कि आरोपी विपिन के पिता नाथीराम की भूमि पर अजय मलिक ने 16 साल का करार करके भट्टा लगाया था जिसके एवज में 80,000 ईटे प्रतिवर्ष देनी तय हुई थी लेकिन अब नाथीराम व उसके पुत्र उक्त जमीन को खाली करवाना चाहता था जिसको लेकर पहले भी उसका अजय मलिक के साथ विवाद हुआ था। इसके साथ ही जांच में सामने आया कि अजय मलिक ने एक भट्टा मुजफ्फरनगर जिले में भी लगाया हुआ है जिसमें तीरथ पाल

को पार्टनर बनाया हुआ था 2016 में अजय मलिक ने नाथीराम की पुत्री की शादी तीरथ पाल के भाई निन्दरपाल से करवाई थी। वहीं बाद में तीरथ पाल और अजय मलिक के बीच पैसों का लेनदेन के लिए विवाद हो गया और अजय मलिक ने तीरथ पाल को हिसाब करने के बाद पार्टनरशिप हटा दिया। उसके बाद तीरथपाल, नाथीराम और उसके पुत्र ईट भट्टे की जगह खाली करवाना चाहते थे। वही पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 2020 में नाथीराम ने अपनी छोटी पुत्री की शादी में अजय मलिक से 14 लाख उधार लिए थे जिन्हें वह वापस नहीं करना चाहता था और उसने अजय मलिक की हत्या की योजना बनाई तथा योजना में शामिल था कि हत्या के केस में फंसने के बाद भट्टे पर रखी दो करोड़ की ईटे बेचकर केस लड़ा जाएगा।

पुलिस ने दोनों आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने सहित 7 अन्य लोगों को हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया है जिसमें अजीत पुत्र नाथीराम, अंकुश पुत्र नाथीराम, नाथीराम पुत्र बुद्ध सिंह, तीरथपाल पुत्र काशीराम, निंदर पाल पुत्र काशीराम, पिंदू पुत्र बिरम सिंह, और सन्नी पुत्र नरेश का नाम शामिल है। जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है।

## उत्तराखंड राज्य को नहीं मिला सवा चार वर्षों में स्थाई मुख्यमंत्री: बेदी

हरिद्वार (आरएनएस)। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता एवं हरिद्वार विधानसभा मीडिया प्रभारी एडवोकेट सचिन बेदी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुए लगभग 29 वर्ष होने जा रहे हैं। इस दौरान उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब तक अलग अलग दलों से 99 जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं, जो कि बड़ा ही आश्चर्य जनक है। प्रैस को जारी बयान में सचिन बेदी एडवोकेट ने कहा कि ज्वेहरा नया काम वहीज के आधार पर राज्य सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में भाजपा की सरकार

है और भाजपा सरकार बने हुए लगभग सवा 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। परंतु भाजपा इन सवा 8 वर्षों में एक भी स्थाई मुख्यमंत्री नहीं दे सकी। भाजपा नेतृत्व द्वारा बार बार मुख्यमंत्री बदलने का खेल खेलकर लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है और राज्य की जनता को धोखा दिया जा रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हो रही है और अपनी साख बचाने के लिए बार बार मुख्यमंत्री बदलकर लोकतंत्र का मजाक बना रही है तथा प्रदेश की भोली भाली जनता को धोखा देने का काम कर रही है। राज्य सरकार जनता

के बारे में कम अपने बारे में ज्यादा सोचती हैं। राज्य में अब से पहले भी भाजपा का शासन रहा, परन्तु भाजपा अपना शासनकाल एक मुख्यमंत्री को लेकर कभी पूरा नहीं कर सकी। प्रदेश की जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों को अब अच्छी तरह से समझ चुकी हैं तथा अब इसके बहकावे में आने वाली भी नहीं है। भाजपा व इसकी जनविरोधी नीतियों से राज्य की जनता का मोह भंग हो चुका है। जिसका जवाब उत्तराखंड राज्य की सम्मानित जनता आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर भाजपा को जवाब देने वाली है।

## राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन ने 11 हजार सैनेटरी पैड उपलब्ध कराये

संवाददाता हरिद्वार। हरिद्वार के प्राथमिक शिक्षकों के एकमात्र पंजीकृत राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिलाधिकारी महोदय को 99 हजार सैनेटरी पैड उपलब्ध कराये जो विभिन्न गांव, शहर के घूमन्तु गरीब परिवारों कि महिलाओ को जिला कार्यक्रम एवं बाल विकास विभाग द्वारा वितरित कराये जाएगे।



आज अपने कैंप कार्यालय पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन हरिद्वार के प्रतिनिधिमण्डल से 99 हजार सैनेटरी पैड प्राप्त करने के बाद जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने यह सामग्री जिला कार्यक्रम अधिकारी देव सिंह के सुपुर्द करते हुए इसके प्रभावी वितरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियों का मुकाबला

आपस में मिल जुलकर ही किया जा सकता है। उन्होंने एसोसिएशन के कार्यों कि सराहना की।

इस अवसर पर एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी को बुके भेंट कर उनके सतत प्रयासों के लिए साधुवाद दिया गया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा की हम शिक्षक हैं तथा हम विद्यालयों तक ही सीमित न रहते हुए अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का भी प्रयास कर रहे हैं।

एसोसिएशन के सदस्यों के सहयोग से आज यह छोटा सा प्रयास सैनेटरी पैड प्रदान कर किया गया है। जिला महामंत्री दर्शन सिंह पंवार ने कहा की पूरे कोरोना काल में एसोसिएशन के लोगों ने फ्रंट लाइन योद्धा के रूप में कार्य किया है वहीं एसोसिएशन की ओर से कोविड पॉजिटिव होने पर हर संभव मदद की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष गोपाल भट्टाचार्य, डॉ. शिवा अग्रवाल, मनोज सहगल एवं शरद भारद्वाज उपस्थित रहे।



## 'द मिनिस्ट्री ऑफ जूनागढ़' में रसिका दुग्गल को मिला अपने गुरु नसीरुद्दीन शाह का साथ

बॉलीवुड फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर एक्ट्रेस रसिका दुग्गल इन दिनों बेहद उत्साहित हैं। जहां एक्ट्रेस की फिल्म को विश्व स्तर पर अब देखा जा रहा है। जी हां हाल ही में उनकी शॉर्ट फिल्म 'द मिनिस्ट्री ऑफ जूनागढ़' को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। इस खास स्क्रीनिंग को लेकर एक्ट्रेस खासा उत्साहित हैं। इससे पहले भी नंदिता दास और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मंटों जिनमें उनका एक अहम रोल था कांस फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है। आपको बता दें, एक्ट्रेस इस भी बेहद खुश हैं क्योंकि शॉर्ट फिल्म 'द मिनिस्ट्री ऑफ जूनागढ़' में उन्हें अपने टीचर नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने का अवसर प्रपात हुआ। नसीरुद्दीन शाह फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट में उनके शिक्षक रह चुके हैं। 1947 में सेट की गई इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है कि रसिका दुग्गल एक ऐसे परिवार के रहस्य का पर्दाफाश करती जिन्होंने एक खूबसूरत लघु संग्रह को रखने का निश्चय कर लिया था। रसिका अब एक बार फिर से बॉलीवुड और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमकर काम कर रही हैं। जहां उन्हें अब अभिनय का दमदार मौका मिल रहा है। आपको बता दें, एक्ट्रेस अपने शिक्षक के साथ काम करके बेहद खुश हैं। जहां वो कहती हैं, कौशल ने बहुत ही सौम्य और सम्मोहक कहानी लिखी है। कहानी कहने में एक संतुलन बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। मुझे इस फिल्म की इसी बात ने आकर्षित किया था, और जाहिर सी बात है मेरे गुरु नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने के अवसर ने भी। मैं जो कुछ भी अपने काम के बारे में जानती हूँ वह बहुमूल्य बुनियादी बातों पर आधारित है, जो मैंने एफटीआईआई में बतौर छात्रा उनसे सीखा है और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। (आरएनएस)

## मदानी से पहले 250 ऑडिशन में रिजेक्ट हुए थे ताहिर राज भसीन

अभिनेता ताहिर राज भसीन का कहना है कि फिल्म मदानी के लिए आदित्य चोपड़ा द्वारा साइन किए जाने से पहले उन्हें लगभग 250 बार रिजेक्ट किया गया था। ताहिर ने कहा, जो कुछ भी सार्थक होता है उसमें समय लगता है और जब मैं पहली बार मुंबई आया तो मुझे यह समझ में आया था। मदानी से तीन साल पहले मुझे लगभग 250 ऑडिशन से खारिज कर दिया गया था, लेकिन मैंने इसे पॉजिटिव ईंधन और प्रतिक्रिया के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा, इसका मतलब था कि मुझे बढ़ने की जरूरत है और विकास वर्कशॉप और घंटों अभ्यास के बाद आता है। अनगिनत रिजेक्शन के बावजूद कभी उम्मीद नहीं खोने वाले ताहिर ने कहा, शक्ति हिट होने में और आगे बढ़ने की इच्छा में निहित है। आज की दुनिया उस सरल संदेश के बारे में है जब हम सभी एक अप्रत्याशित समय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। साहस के साथ आने वाले समय में परीक्षा के लिए खुद को बेहतर, फिट और मजबूत बनाते हैं। ताहिर लूप लपेटा में तापसी पन्नू के साथ रोमांटिक लीड के रूप में दिखाई देंगे। बुलबुल तरंग में सोनाक्षी सिन्हा और ये काली काली आंखों के साथ वह श्वेता त्रिपाठी के साथ नजर आएंगे। वह कबीर खान की 83 में भी दिखाई देंगे, जिसमें वह एक महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 1983 भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप की जीत की कहानी है और इसमें रणवीर सिंह अंडरडॉग टीम के कप्तान कपिल देव के रूप में नजर आएंगे।

## ये तो अच्छी बात है अगर मैं दीपिका के जैसी लगती हूँ: अमाला पॉल

दीपिका पादुकोण की खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी एक हमशकल है जो उनके जैसी दिखती हैं। दीपिका के जैसी दिखने वाली ये एक्ट्रेस का नाम है अमाला पॉल जो कि साउथ की एक्ट्रेस हैं। वह अपनी बॉल्ड फोटोज को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। अमाला पॉल तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अमाला ने जब इंटरव्यू में कदम रखा तब दीपिका से उनके लुक्स मिलने की वजह से वह काफी चर्चा में आई थीं। अमाला काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। वह कई बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीत चुकी हैं। अमाला ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि ये तो अच्छी बात है अगर वह दीपिका के जैसी लगती हैं। उन्होंने कहा था, दीपिका बहुत खूबसूरत हैं। अमाला पॉल को प्रभु सोलमन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैना (2010) ने उन्हें इंडस्ट्री में एक बड़ी पहचान दिलाई। इस फिल्म पर रिलीज से पहले ही बहुत उम्मीद लगा रखी थी। मैना की सफलता के बाद, अमाला को 2011 के नए सुपर स्टार के रूप में जाना गया, उन्होंने बाद में कई प्रमुख फिल्म पर हस्ताक्षर किए। इसने स्क्रीन पर नाम अमाला पॉल को अनाख द्वारा बदल दिया, क्योंकि एक अन्य अभिनेत्री अमला अक्किनेनी ने पहले से ही फिल्म इंस्ट्री में अपना नाम कमाया था। 2010 में उसने अपना नाम वापस स्क्रीन पर बदल लिया, अनाखा से असली नाम अमाला पॉल कर दिया। अमाला पॉल की पसंदीदा के बारे में बात करें तो उनकी पसंदीदा रंग गुलाबी है उनकी पसंदीदा अभिनेता आमिर खान और अमिताभ बच्चन जी है और उनकी पसंदीदा अभिनेत्री कैथरीन हेपबर्न है। अगर हम उनकी फेवरेट डिश के बारे में बात करें तो उन्हें बिरयानी बहुत ही पसंद है। (आरएनएस)

## अक्षय कैटरीना की फिल्म सूर्यवंशी 15 अगस्त को रिलीज हो सकती है

पिछले एक साल से रिलीज के लिए अटकी बॉलीवुड कलाकार अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी का दर्शक पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सूर्यवंशी फिल्म पिछले साल मार्च के महीने में ही रिलीज होने वाली थी। लेकिन अचानक कोरोना वायरस के कहर की वजह से इस फिल्म को मेकर्स ने अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था। कोरोना वायरस के कहर के बाद मेकर्स ने पिछले साल ही ऐलान कर दिया था और कहा था कि सूर्यवंशी फिल्म 2021 की अप्रैल के महीने में रिलीज होगी। लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से फिल्म की रिलीज को टालना पड़ा था।

अब उम्मीद की जा रही है कि देश के हालात सामान्य होंगे और जल्द ही सिनेमाघर खुलेंगे। ऐसे में ताजा खबरों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म सूर्यवंशी इसी साल अगस्त के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है।



इस वक्त की आई ताजा खबरों के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि रिलायंस एंटरटेनमेंट इस तारीख और सिनेमाघरों में फिल्म की रिलीज के बारे में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बातचीत कर रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यवंशी फिल्म ओटीटी पर नहीं बल्कि सीधे सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल जब फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया था तो इसको

दर्शकों की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिला था। जिसके बाद फैंस सूर्यवंशी की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि फिल्म की रिलीज दो बार टल चुकी है। हो सकता है कि इस साल 15 अगस्त के मौके पर सूर्यवंशी रिलीज की जा सकती है। फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और अजय देवगन कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं। (आरएनएस)

## 'धाकड़' के लिए अर्जुन रामपाल ने करवाया अपना मेकओवर



बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अर्जुन रामपाल ने हाल ही में अपने लुक के साथ एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया है जो अब उनके फैंस को खासा पसंद आ रहा है। एक्टर ने अपनी खुद की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे

उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। आप भी देखिए एक्टर के इस न्यू मेकओवर की बेहतरीन तस्वीरें।

इस नए हेयरस्टाइल में अर्जुन रामपाल बेहद स्टाइलिश लग रहे हैं। एक्टर का ये खास मेकओवर बॉलीवुड के मशहूर

हेयरस्टाइलिस्ट आलिम हाकीम ने किया है। जहां उन्होंने अपने बालों को ब्लॉन्ड करवाया है।

शॉर्ट बालों के साथ ये ब्लॉन्ड अंदाज एक्टर पर काफी शूट कर रहा है। आपको बता दें, एक्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जहां उन्हें आलिम हाकीम के हेयर स्टूडियो के बाहर ही स्पॉट किया गया था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टर के फैंस उनके लुक्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। जहां सभी लगातार कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें, एक्टर ने अपना ये लुक कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के लिए तैयार किया है। जिसमें वो बेहद दमदार अंदाज में नजर आएंगे। वहीं एक्टर हमें अपनी अगली फिल्म नेल पॉलिश में भी नजर आएंगे। (आरएनएस)

## कृति खरबंदा ने बॉलीवुड में पूरे किए 12 साल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने बॉलीवुड में 12 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने शनिवार को प्रशंसकों के साथ यात्रा के बारे में अपना अनुभव साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। कृति ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 12 साल पहले, 12 जून को, मैंने एक यात्रा शुरू की थी। एक किशोरी के रूप में, मैंने इस उद्योग में अपना पहला कदम रखा, जिसने आखिरकार मुझे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया, जो मैं आज हूँ।

उन्होंने लिखा, एक अभिनेता के रूप में अपने समय में, मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ और मैं उनकी आभारी हूँ। मैंने सबक सीखा और अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी कॉलिंग टूंडी, यह मेरी पहचान बन गई। मुझे विशेषाधिकार मिला है उद्योग के कुछ बेहतरीन लोगों के साथ काम करने के लिए। इसलिए, मेरे करियर से जुड़े सभी लोगों के लिए- चाहे वह एक मिनट के लिए हो, एक दिन के लिए, या पिछले 12 वर्षों के लिए, मेरे पास आपके लिए आभार के अलावा कुछ नहीं है।

अभिनेत्री ने साझा किया, प्रगति से डॉ. स्वाति तक, आरती शुक्ला से लेकर राजकुमारी मीना तक, और अब अदिति, कहीं न कहीं मैं बड़ी हुई हूँ। मैं एक अपरिपक्व किशोरी से एक ऐसी वयस्क जो डरपोक से मजबूत और बॉल्ड बनी है। मैं बच्ची थी जो 90 के दशक में किकपैस नंबरों पर ड्रेस अप और डांस करना पसंद करती थी और अब मैं जीने के लिए ऐसा करती हूँ। मैं इससे बड़े आशीर्वाद की कल्पना नहीं कर सकती। आज मैं एक पूरी पीढ़ी को देखती हूँ और अपने नंबरों पर अधिक प्रदर्शन करती हूँ, जो मेरे पास है उसे फिर से बनाने के लिए भावना असली है। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उन्होंने आगे लिखा, यह शब्दों में बयां करना कठिन है कि मैं कितना आभारी महसूस करती हूँ। मैं अपने परिवार, मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षकों के समर्थन के बिना यहाँ नहीं होती, जिन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मेरी किस्मत में बड़ी चीजें हैं। मेरे प्रशंसकों और फैन क्लबों के लिए भी बड़ा आभार। आप लोग मुझ पर तब भी विश्वास करते हैं, जब मुझे संदेह होता है, और यही मेरे लिए बेहतर

करने और खुद पर और विश्वास करने की प्रेरणा बन जाता है। आप लोग मुझे ऐसा महसूस कराते हैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूँ।

युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, कृति ने लिखा, जब दुनिया रोमांचक और ग्लैमरस दिखती है, तो यह कठिन और ज्यादा कठिन होती है। लेकिन फिर क्या नहीं है, यह मेरा 24/7 है! मैं जो बन गई हूँ मैं उससे प्यार करती हूँ। साधारण मध्यम वर्ग की लड़की महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी हो गई है! अगर कोई इसे पढ़ रहा है और इस बात से अनजान है कि उसे किस रास्ते पर जाना है, तो मुझे आशा है कि मेरी कहानी आपकी अच्छी मदद करेगी और आपको भी उस मौके को लेने का आत्मविश्वास मिलेगा और आप जो प्यार करते हैं उसे करने में सीधे कूदें। हो सकता है कि 12 साल बाद आप खुद को पाएंगे कि मैं आज कहां हूँ। कृतज्ञता से अभिभूत और उत्साह के साथ गदगद! इस भावना की कई सालों से इंतजार कर रही हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद! (आरएनएस)

# एकीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य तंत्र बनाने की जरूरत

सोहम डी भादुड़ी

विश्व के ज्यादातर मुल्कों के पास सरकारी और निजी क्षेत्र के नाना प्रकार के सम्मिलित स्वास्थ्य सेवाओं वाले तंत्र मौजूद हैं। इन दोनों क्षेत्रों के ध्येय में कितना समन्वित एवं साझा प्रयास है, इससे किसी सफल स्वास्थ्य तंत्र का पता चलता है। इस किस्म का उभयनिष्ठ प्रयास बताता है कि निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य उद्देश्यों और तरजीहों के कितनी अनुरूप हैं। ऐसे एकीकरण की सार्थकता कोविड-19 जैसी महामारी के वक्त और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब समूचे स्वास्थ्य तंत्र को राष्ट्रीय हित की खातिर साझी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कोई हैरानी नहीं कि कोविड-19 प्रबंधन में भारतीय स्वास्थ्य तंत्र ने नागरिकों को बुरी तरह निराशा किया है क्योंकि यह हमारी व्यवस्था का रिवायती गुण-दोष जो ठहरा। वैश्विक महामारी से पहले ही भारतीय स्वास्थ्य तंत्र में एक ओर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं जर्जर अवस्था में थीं तो दूसरी तरफ निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बिना किसी नियंत्रण वाली व्यवस्था के रूप में चली आ रही है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में दोनों क्षेत्रों के बीच साझा तालमेल बन पाए, इस हेतु दशकों से कई मर्तबा अल्पकालीन, टुकड़ों में, लेकिन ज्यादातर समय आधे-अधूरे प्रयास किए गए हैं, जो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य तंत्र बनाने के लिए नाकाफी रहे। यही समय है जब मौजूदा आपदा से इस ओर सबक लें। वर्ष 2000 के पहले दशक के आरंभिक वर्षों में, गरीबों को इलाज पर हुए खर्च की भरपाई हो सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने जनस्वास्थ्य बीमा

योजना (पीएचआई) शुरू की थी। इस वर्ग में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नवीनतम केंद्रीय योजना है। वर्ष 2018 तक कम से कम 31 राज्यस्तरीय पीएचआई योजनाएं चल रही थीं।

इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल गरीबों की जेब पर इलाज पर होने वाले भारी भरकम बोझ से बचना बल्कि निजी अस्पताल की सेवाओं का इस्तेमाल, नियमन कर एक युक्तिपूर्ण विकल्प बनाना है। तथापि आगाज के लगभग बीस साल बीत जाने के बाद भी वास्तविक धरातल पर बहुत कम हासिल हो पाया है। इस कहानी को बताने के लिए तीन बड़े अवयवों की मदद लेंगे। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे रिपोर्ट (2017-18) के मुताबिक देश के शहरी क्षेत्र में केवल 8.9 प्रतिशत तो ग्रामीण अंचल में मात्र 12.9 फीसदी सरकार-प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाई जा सकी है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्यों में हालिया एनएफएचएस-5 (वर्ष 2019-20) का अनुमान बताता है कि इन सूबों में भी केवल 30 प्रतिशत जनसंख्या ही किसी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आ पाई है। यह हाल तब है जब वहां लगभग एक दशक से जनस्वास्थ्य बीमा योजना लागू है।

दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है, स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी कम रही है, कहने की जरूरत नहीं कि इस दौरान सरकारी अस्पतालों की कारगुजारी तो और भी कमजोर रही। निजी अस्पतालों में अमूमन केवल 3 फीसदी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनस्वास्थ्य योजना से

जुड़े हैं। इससे हो रहा है कि देशभर में अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करवाने वालों में ज्यादातर को निजी क्षेत्र का रुख करना पड़ता है। जनस्वास्थ्य बीमा योजना अपना मकसद पाने में विफल रही है, जिसका उद्देश्य था कि आमजन भी अच्छी निजी स्वास्थ्य सेवाओं की कीमत चुकाने लायक बन पाए और जिन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, वहां जाने में निजी क्षेत्र दिलचस्पी ले।

तीसरा और आखिरी पहलू है, बृहद स्वास्थ्य सूचना बुनियादी ढांचे का निर्माण, यह व्यवस्था निजी क्षेत्र के अस्पतालों के साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की अर्थपूर्ण सहकार्यता बनाने की धुरी बन सकती है। हाल ही में यहां-तहां बिखरी पड़ी स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को इकट्ठा कर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विलक्षण स्वास्थ्य पहचान व्यवस्था बनाने के काम ने जोर पकड़ा है। लेकिन देश में जनस्वास्थ्य बीमा योजना तक बहुत कम लोगों की पहुंच होने के कारण इसका प्रयोजन अत्यंत सीमित बना हुआ है।

जनस्वास्थ्य बीमा योजना में नागरिकों की कम भागीदारी भी इन कमियों में एक मुख्य कारण है। तथापि यदि दृष्टिकोण की कमी हो तो धन कितना भी रखा जाए, वह कारगर नहीं हो पाता। वक्त-वक्त पर आई विभिन्न सरकारों ने इन योजनाओं को एक वास्तविक राष्ट्रीय स्वास्थ्य तंत्र निर्माण का साधन बनाने की बजाय लोकलुभावन औजार की तरह इस्तेमाल किया है।

निजी मेडिकल क्षेत्र के आचरण पर नियामक व्यवस्था न होने की वजह से निजी क्षेत्र के अस्पतालों की बाह्य रोगी सेवाओं

तक आमजन की पहुंच हो सके, इसकी संभावना अभी क्षीण है। कुल मिलाकर नतीजा यह कि कोविड-19 महामारी के दौरान दीगर अस्पतालों में गलत आचरण और अव्यवस्था चंडुओर फैली हुई है। भारत के पास विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर काम करने का चार दशकों का लंबा अनुभव है। फिर भी, दुनिया की बेहतर स्वास्थ्य बीमा सरीखी योजनाओं की बनिस्पत हमारा यहां का तरीका टुकड़ों में बंटा, चंद सेवाओं तक सीमित और अदूरदर्शी है। जहां अक्सर निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपना फर्ज छोड़ देने का इल्जाम लगता है वहीं सरकारी रवैया भी इससे कुछ अलग नहीं है। ज्यादातर सरकारें अपनी ओर से सहायता या निगरानी व्यवस्था बैठाने की बजाय सार्वजनिक-निजी साझेदारी को औजार बनाकर सारी जिम्मेवारी निजी क्षेत्र पर डालना चाहती हैं। पीपीपी योजना के अंतर्गत देशभर में फैले छोटे संभावित भागीदार, जो भारतीय निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं, की बजाय बड़े खिलाड़ी छापे हुए हैं। मौजूदा कोविड-19 टीकाकरण नीति भी हमारे तौर-तरीकों का बढिया उदाहरण है। कुल टीकों का 25 फीसदी कोटा निजी क्षेत्र के अस्पतालों के लिए रखा गया है, जो अनुपात के हिसाब से एकदम बेजा है। क्योंकि केवल चंद बड़े निजी अस्पताल ही इतनी बड़ी तादाद को वास्तव में संभालने लायक होंगे। हालांकि हाल ही में छोटे निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की तर्कसंगत आपूर्ति नीति उलीकी गई है, लेकिन यह बहुत देर से आई है।

## रियल लाइफ में फैशन क्वीन है सामंथा अक्किनेनी

द फैमिली मैन सीजन 2 से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे सामंथा अक्किनेनी काफी सुर्खियों में हैं। इस सीरीज में हर किरदार को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। सभी कलाकारों ने लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। लेकिन राजी का किरदार निभाने वाली खूबसूरत अफसर समंथा अक्किनेनी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। यह साउथ इंडस्ट्री की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। इनका नाम साउथ सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अदाकारा में शुमार है। द फैमिली में के साथ इस अभिनेत्री ने हिंदी जगत में अपना कदम रखा है। इस सीरीज में उनके द्वारा निभाई गई राजी की भूमिका बहुत ही लाजवाब है। इस वेब सीरीज में यह अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है।

बता दें समानता जितनी प्यारी और भोली भाली दिखते हैं असल जिंदगी में यह अभिनेत्री उतनी ही स्टायलिश है। इंडियन हो या फिर वेस्टर्न यह अभिनेत्री अपने हर लुक को बहुत ही अच्छी तरह से केयर करती हैं। फैशन के मामले में इस अभिनेत्री की कोई टक्कर नहीं दे सकता। सोशल मीडिया पर जब भी इनकी तस्वीरें पोस्ट होती हैं, तो फैंस देखते ही रह जाते हैं। इनकी हर तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल होती है। फैंस इनकी तस्वीरों को बेहद पसंद करते हैं। फैंस से लेकर इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी भी इनकी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। फैमिली मैन 2 की एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी असल जिंदगी में काफी बोलड और बिंदास है।

**सू- दोकू क्र.129**

	7			1		3	
1		9				5	
			3			1	
		5				3	
3				2		5	
			3			2	
	4					7	
7		8		1		6	
	6		7		9		1

**नियम**

- कुल 81 वर्ग है, जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
- हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
- बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

**सू-दोकू क्र.128 का हल**

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

## निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 'सुपर स्पेशलिटी न्यूरो कैंप' का आयोजन

संवाददाता

हरिद्वार। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित स्वामी रामप्रकाश चैरिटेबल हास्पिटल निकट अवधूत मंडल आश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत "सुपर स्पेशलिटी न्यूरो कैंप" आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा शिविर में आये डेढ़ सौ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परिक्षण किया। शिविर में डा.राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ न्यूरो सर्जन डा.शरद पांडे एवं डा.पंकज पांडे के साथ ही एलएलआरएम मेडिकल कालेज मेरठ के आर्थोपेडिक सर्जन डा.प्रियंक अग्रवाल, मनोरोग विशेषज्ञ डा.नीतू, बरेली से डा. राज कुमार गुप्ता, डा.नवीन ने स्वास्थ्य परिक्षण किया।

स्वास्थ्य शिविर में डा.राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरि.न्यूरो सर्जन डा.शरद पांडे ने शिविर में एक मरीज के सिर की ब्राह रसौली की सर्जरी भी की। चिकित्सालय के निदेशक लै.कर्मल (सेनि) डा.प्रवीण रेड्डी ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत "सुपर स्पेशलिटी न्यूरो कैंप" में अपनी सेवाएं देने के लिये पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों के प्रति आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हुये कहा कि इस तरह आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविरों से स्थानीय ही नहीं अपितु निकटवर्ती जनपदों के लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय द्वारा संत समाज व निर्धनों



को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्स रे व अन्य जांच न्यूनतम दरों पर कराई जाती हैं।

इस अवसर पर स्वामी रामप्रकाश चैरिटेबल हास्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डा.संजय शाह ने बताया कि चिकित्सालय अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आमजन की सेवा के लिये उपलब्ध है। चिकित्सालय में समय-समय पर जनहित में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किये जा रहे हैं जिसका क्षेत्र के लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है।

डा.शाह ने बताया कि भविष्य में भी प्रत्येक रविवार को इसी प्रकार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर (सुपर स्पेशलिटी कैंप) आयोजित कर विशेषज्ञ चिकित्सकों को आमंत्रित किया जायेगा जिसका कि क्षेत्र के जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा लाभ

मिल सके।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कुल 153 लोगों ने स्वास्थ्य परिक्षण कराते हुये उपस्थित वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया।

शिविर समापन अवसर पर चिकित्सालय के निदेशक लै.कर्मल (सेनि) डा.प्रवीण रेड्डी व डा.संजय शाह ने विशेषज्ञ न्यूरो सर्जन डा.शरद पांडे एवं डा.पंकज पांडे, आर्थोपेडिक सर्जन डा. प्रियंक अग्रवाल, मनोरोग विशेषज्ञ डा. नीतू, डा.राज कुमार गुप्ता, डा.नवीन ने स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद दिया।

इस दौरान डा.बी.डी.जोशी, डा.विवेक, निधि धीमान, पार्षद परविंदर गिल, समाजसेवी योगेश पांडे आदि उपस्थित रहे। शिविर में ब्लड शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जांच के साथ ही रोगियों को मुफ्त दवा दी गयी।

## बार-बार मुख्यमंत्री बदल भाजपा भ्रष्टाचार को छुपाने की कर रही है कोशिश: यूकेडी



संवाददाता

देहरादून। राज्य की सत्तासीन भाजपा राज्य को गर्त की ओर ले जा चुकी है। स्थिर सरकार न होने के कारण सरकार की कार्यशैली संदेह के घेरे में रही है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्थाओं की पोल कोरोनाकाल में जनता देख चुकी है। राज्य सरकार कोरोना किरट तक मरीजों को उपलब्ध नहीं करा सकी। कुंभ में कोरोना जांच में हुई अनियमितताओं से स्पष्ट होता है कि एक बड़ा घोटाला सरकार कोरोना इलाज व कुंभ में कर चुकी है। बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना भाजपा कही न कही भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही है। जबकि इनका ये रवैया जनता का सबसे बड़ा अपमान है।

प्रेस वार्ता के दौरान यह बात आज यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष बी.डी. रतूड़ी द्वारा कही गयी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल भाजपा के भ्रष्टाचार को जनता के बीच जाकर पोल खोलेगा। उन्होंने कहा कि उक्रांद अन्य सभी समान्तर विचारधारा के संगठनों से बात कर व सभी को एक मंच पर लाकर 2022 विधानसभा चुनाव में जायेगा। उन्होंने कहा कि दल का द्विवार्षिक महाअधिवेशन जिसमें संगठन का चुनाव किया जाना है दिनांक 24 व 25 जुलाई 2021 जो कि दल का स्थापना दिवस भी है देहरादून में किया जाना है। उक्रांद जल, जंगल, जमीन, धारा 371, 73 वां व 74 वां पंचायती राज अधिनियम लागू करके पंचायतों को पूरे अधिकार देना, मूल निवास सन 1980 से पूर्व राज्य निवासी को परिभाषित करना, पर्यटन के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य का पर्यटन चौपट हो गया। स्टे होम सब बन्द है। पर्यटन से जुड़ा रोजगार खत्म हो चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मदद करे।

रतूड़ी ने कहा कि आगामी परिसीमन जो 2026 में होना है जिसमें राज्य की अवधारणा जो रखी थी वह खत्म हो जायेगी। पहाड़ की विधानसभा सीटों की संख्या घटकर मैदानी जनपदों से जुड़ जायेगी। इसके लिये हमने बलिदान व संघर्ष नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उक्रांद जनता को लामबद्ध करके व चुनाव में मुद्दा बनाकर चलेगा। प्रेस वार्ता में लताफत हुसैन, डी डी शर्मा, जयप्रकाश उपाध्याय व सुनील ध्यानी उपस्थित थे।

## तेज धमाके से उड़ी रसोई की छत, ग्रामीणों में दहशत

काशीपुर (आरएनएस)। गांव मड़ैया हट्टू के एक घर की रसोई में हुए तेज धमाके से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बताते हैं कि धमाके के बाद घर में मौजूद सभी लोग भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी। प्रधान की सूचना पर केलाखेड़ा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। केलाखेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाली बेरिया दौलत चौकी के गांव मड़ैया हट्टू में काला सिंह और सोनू सिंह परिवार के साथ रहते हैं। देर शाम काला सिंह की रसोई में तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। पड़ोसियों के मुताबिक, जब वे लोग धमाके की आवाज सुन घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग घायल अवस्था में वहां से निकलकर तेजी से भाग गये। काला सिंह और सोनू सिंह भी परिवार समेत फरार हो गये। इन दोनों के भागने से ग्रामीण सकते में आ गये। इन लोगों ने इसकी सूचना प्रधानपति विश्वजीत संधू को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रधानपति ने बेरिया चौकी इंचार्ज मनोहर सिंह को घटना की जानकारी दी। केलाखेड़ा एसओ बीसी जोशी, बेरिया चौकी इंचार्ज मनोहर चंद टीम के साथ पहुंचे। टीम ने छानबीन की और पड़ोसियों से पूछताछ भी की। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने धमाके की आवाज दूर तक सुनी थी।

## वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो सांध्य दैनिक दून वैली मेल के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

## आवासीय भूमि को आबादी में घोषित कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन

संवाददाता

देहरादून। ग्राम गल्जवाड़ी में वर्षों से रह रहे ग्राम वासियों की आवासीय भूमि को राजस्व अभिलेखों में आबादी में दर्ज कराने के लिए शासनादेश घोषित किए जाने की मांग को लेकर आज ग्राम वासियों द्वारा ग्राम प्रधान लीला शर्मा के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है।

ज्ञापन के माध्यम से ग्राम वासियों ने कहा है कि वह पिछले 70 वर्षों से यहां रह रहे हैं, ग्राम वासियों की जमीन आबादी क्षेत्र में घोषित किए जाने को लेकर पिछले 15 सालों से संघर्षरत है कहा गया है कि ग्राम के लगभग 350 परिवार भूमि के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस संबंध में ग्राम वासियों द्वारा कई मर्तबा जिलाधिकारी देहरादून व मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थित होकर अपनी समस्या से अवगत कराया गया है। कहा गया है कि प्रत्येक बार हम ग्राम वासियों की भूमि को आबादी में घोषित करने का आश्वासन ही मिलता रहा है। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की घोषणा से ग्राम गल्जवाड़ी में रह रहे परिवारों की भूमि को आबादी भूमि घोषित कराने की घोषणा की गई थी किंतु उस पर भी कोई संतोषजनक



कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम वासियों ने ग्राम गल्जवाड़ी की भूमि को आबादी भूमि घोषित कराने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद दायर किया था। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को ग्राम वासियों की भूमि को आबादी घोषित करने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया। किंतु काफी समय व्यतीत होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा ग्राम वासियों की भूमि को अभी तक आबादी भूमि घोषित नहीं किया जा सका है। कहा गया है कि सरकार द्वारा वर्ष 2015 में आबादी क्षेत्र दर्शाने की अधिसूचना जारी की गई थी उसके बाद भी ग्राम गल्जवाड़ी में बसे आबादी भूमि पर सैकड़ों परिवारों को

उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है और आबादी भूमि खसरा नंबरों को शासन द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित किया गया है। कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने भी उत्तराखंड शासन को गल्जवाड़ी की भूमि को आबादी भूमि को दर्शाने हेतु आदेश जारी किए गए थे इसके बावजूद भी शासन द्वारा आबादी भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध करते हुए कहा है कि आवासीय भूमि क्षेत्र को आबादी क्षेत्र की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने की कृपा करें तथा राजस्व अभिलेखों में आबादी भूमि जल्द से जल्द दर्ज कराने के लिए शासनादेश पारित किया जाये।

## नेशनल सीनियर सिटीजन डे पर दून में होगा भव्य कार्यक्रम: जोशी

नगर संवाददाता

देहरादून। सिनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी देहरादून की एक आम सभा आज राजपुर रोड स्थित एक होटल में हुई। सभा की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष डा. अतुल जोशी ने की।

बैठक में समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने अपने समाज के वरिष्ठ लोगों के कल्याणार्थ विषयों पर गंभीर चर्चा की गई। सभा में एस.पी.कोचर, ब्रिगेडियर के.जी.बहल, डा. अतुल जोशी, डॉ पी.

डी.जुयाल, डा. ए.एस.नेगी, के.के.ओबरॉय, अविनाश मनचंदा, अतुल चुघ, सुशीला



बलूनी, जितेंद्र डंडोना, अश्वनी मित्तल, जुगल किशोर वर्मा मशाल, जी.एस.नेगी, एच.एस.रजवाड़ आदि प्रतिष्ठित लोगों ने

अपने-अपने विचार रखे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के हित को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए जिसमें सबसे बड़ा निर्णय आगामी 21 अगस्त को नेशनल सीनियर सिटीजन डे के उपलक्ष्य में देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ-साथ वरिष्ठजनों की मेडिकल सुविधाओं के विषय पर भी चर्चा की गई।

## शासन ने पीआरडी जवानों हेतु रोस्टर लागू करने का दिया निर्देश: मोर्चा

मोर्चा ने मुख्य सचिव से किया था रोस्टर लागू किए जाने का आग्रह

संवाददाता

विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पीआरडी जवानों के कल्याण हेतु सबको रोजगार दिए जाने की दशा में सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्वयंसेवक/ जवान को 6-6 माह का रोजगार दिए जाने का उल्लेख था, लेकिन 16 वर्ष बीतने के उपरांत भी रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया गया।

नेगी ने कहा कि रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने हेतु मोर्चा द्वारा मुख्य सचिव से आग्रह किया गया था, जिसके



क्रम में शासन द्वारा निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल को रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। रोस्टर लागू न होने के कारण सिफारिश विहीन स्वयंसेवक दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं तथा वहीं दूसरी ओर अधिकारियों से सांठगांठ कर

सेटिंग बाज निरंतर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। नेगी ने कहा कि रोस्टर लागू न होने से विभाग में न तो पारदर्शिता बनी हुई है और न ही प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को शासनादेशानुसार रोजगार मिल पाता है। पत्रकार वार्ता में- सुशील भारद्वाज व जाबिर हसन मौजूद थे।



# कोरोना से डरे नहीं

# सतर्क रहें, सुरक्षित रहें



एक नजर

## शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता आमिर-किरण की तरह: संजय राउत

नई दिल्ली। सोमवार को शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने एक दिलचस्प बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना और भाजपा का रिश्ता आमिर खान और किरण राव के रिश्ते की तरह है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए एक बयान पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने कहा कि हम (बीजेपी-शिवसेना) भारत-पाकिस्तान की तरह नहीं हैं। आप आमिर खान और किरण राव को देखिए, हम उनकी तरह हैं।



हमारे राजनीतिक रास्ते भले ही अलग हैं, लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी सलामत है। बता दें कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि बीजेपी-शिवसेना कोई दुश्मन नहीं हैं, भले ही हमारे बीच मतभेद हो सकता है। फडणवीस के इसी बयान पर संजय राउत ने अपने ही अंदाज़ में जवाब दिया। गौरतलब है कि हाल ही में बॉलीवुड स्टार आमिर खान और किरण राव का तलाक हुआ है। लेकिन दोनों ने अपने साझा बयान में कहा है कि भले ही उनका रिश्ता अलग हो रहा है, लेकिन वो दोस्त रहेंगे और अपने बच्चे की देखभाल करेंगे। शिवसेना और बीजेपी के बीच काफी लंबे वक्त से कुछ पकने की खबरें आ रही हैं। पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उसके बाद संजय राउत ने भी पीएम मोदी की तारीफ की थी, वहीं दोनों पार्टियों के नेताओं के बयानों में एक-दूसरे के लिए तल्खी भी कम हुई थी।

## ‘सच कभी खामोश नहीं रह सकता’

नई दिल्ली। राफेल सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराए जाने की कांग्रेस की मांग के बीच पार्टी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने सोमवार को अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राफेल डील, मोदी सरकार और अंबानी का नाम लिया गया है। ये वीडियो एक टीवी चैनल का है। जिसको शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि सच कभी भी खामोश नहीं रह सकता, शमोडिया के विपरीत। पतराफेल घोटाला। इससे पहले राहुल गांधी ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण करते हुए रविवार को लोगों के लिए सवाल पोस्ट किया कि मोदी सरकार इस जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर किए गए सवाल के उत्तर के लिए चार विकल्प दिए— अपराधबोध, मित्रों को बचाना है, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए या उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। गांधी ने सवाल पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, शमोदी सरकार जेपीसी की जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है?— अपराध बोध, मित्रों को भी बचाना है, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए और ये सभी विकल्प सही हैं। श्र गांधी राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लंबे समय से लगाते रहे हैं और उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था। इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था।



## अनिश्चित काल के लिए बंद हुआ दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट!

नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते लाजपत नगर मार्केट को बंद करने को कहा है। डीडीएमए ने अपने जारी निर्देश में कहा है कि अगले आदेश तक लाजपत नगर मार्केट बंद रखा जाएगा। साथ ही डीडीएमए ने लाजपत नगर मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और पूछा है कि कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर क्यों उनके खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। इस बीच दिल्ली में लगाकार अनलॉक की प्रक्रिया भी जारी है। दिल्ली में 5 जुलाई से स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दे दी गई। हालांकि सिनेमा हॉल, स्पा, मल्टीप्लेक्स आदि अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के कार्यक्रमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। इससे पहले पिछले हफ्ते डीडीएमए ने जिम और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही बारात घरों और होटलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी गई थी।



# रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द करें शुरु: धामी

## सीएम ने ली बीजापुर अतिथि गृह में अधिकारियों की बैठक



नगर संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजापुर अतिथि गृह में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिये कि राज्य में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाय। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही

पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाय। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु में एक साल छूट प्रदान करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि

## प्रदेश के नए मुखिया से पुलिस कर्मियों को बड़ी आस

नगर संवाददाता देहरादून। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर पुलिस विभाग में खुशी की लहर दिख रही है। अब पुलिस कर्मचारियों को उम्मीद जाग गई है कि उन्हें 4600 ग्रेड पे मिल सकता है।

इसके पीछे का कारण यही माना जा रहा है कि विगत 16 मई 2021 को विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 4600 ग्रेड पे दिए जाने को लेकर सीएम को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे दिए जाने के लिए समर्थन किया था। इसके साथ ही महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें मनोबल बनाए रखने की बार कही थी।

उस दौरान खटौती विधायक पुष्कर सिंह धामी के लेटर पर लिखा यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही अब जब धामी सीएम बन गए हैं तो पुलिस कर्मियों को भी ग्रेड पे की मांग जल्द पूरी होने की आस जग गयी है।

## उत्तराखंड निवास में जमे कर्मचारियों को हटाया जाए: मनीष

नगर संवाददाता देहरादून। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय संयोजक व पूर्व राज्य मंत्री मनीष कुमार ने एक बयान में कहा कि उत्तराखंड निवास में जो कर्मचारी और अधिकारी वर्षों से जमे हुए हैं, उनको तत्काल हटाया जाए।

मनीष कुमार का कहना है कि उत्तराखंड निवास में राज्य आंदोलनकारियों को कभी भी कमरा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से हमेशा कमरा उपलब्ध नहीं होने की बात ही कही जाती है। जबकि वहां कई कमरे खाली रहते हैं। मनीष कुमार ने कहा कि क्या कारण है कि वर्षों से अधिकारी और कर्मचारी यहां पर जमे हुए हैं। उन्होंने सीएम से मांग की है कि तत्काल इस पर कार्यवाही करें। अगर शीघ्र ही इन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो हम लोग आंदोलन करने को विवश होंगे।

## विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाएं सीएम: धीरेन्द्र



नगर संवाददाता देहरादून। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रदेश के नए मुखिया से विधानसभा का एकदिवसीय आपातकालीन सत्र बुलाए जाने की मांग की है।

आज कांग्रेस भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध जानकारी की नौकरियों को वैधानिक स्वीकृति दिलाई जाने हेतु तत्काल विधानसभा का एक दिवसीय आपातकालीन सत्र बुलाए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी, कांग्रेस देहरादून अध्यक्ष लालचंद शर्मा और पूर्व राज्य मंत्री मनीष कुमार की उपस्थिति में पत्रकारों से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत राज्य बना है, लेकिन साढ़े चार साल तक प्रदेश में राज करने वाले भाजपा के दोनों मुख्यमंत्रियों ने आंदोलनकारियों के हित में कदम उठाना वाजिब नहीं समझा।

धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने देहरादून में शहीद स्मारक पर एक दिवसीय आपातकालीन सम्मेलन बुलाकर फैसला किया है कि सरकार के जन विरोधी रवैया के विरुद्ध 14 जुलाई को राज्यपाल के आवास का घेराव किया जाएगा। यदि फिर भी फैसला ना हुआ तो राज्य आंदोलनकारी आगामी 8 अगस्त को क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कहा कि कांग्रेसी अध्यक्ष प्रीतम

प्रदेशवासियों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पूरी योजना बनाई जाय। उन्होंने कहा कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी पुख्ता व्यवस्थाएं रखी जाए। सीएचसी एवं पीएचसी स्तर तक ऑक्सीजन कन्सट्रेंटर, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द वर्द्धन, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, सौजन्या, एस.एन. पाण्डेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव अरूणेंद्र चौहान, सचिव अधिनस्थ सेवा चयन आयोग संतोष बडोनी उपस्थित थे।

सिंह ने भी राज्य में हो कार्यों के साथ राज्य में भाजपा सरकार के चलते हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता की व्यक्त की है और कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों की फरमान का कांग्रेस समर्थन करेगी। धीरेन्द्र प्रताप ने भाजपा के एक विधायक पर एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप पर कहा कि सीएम पहले दिन से ही अच्छे काम करने की शुरुआत का दावा कर रहे हैं, तो वह क्यों नहीं सबसे पहले भाजपा के विधायक के विरुद्ध केस दर्ज किया जाए।

कहा कि उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत में शनिवार से पहले नेता प्रतिपक्ष के मामले पर कांग्रेस ने अपना निर्णय घोषित कर देगा। कहा कि पंजाब और छत्तीसगढ़ में भाजपा नेतृत्व कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है इसलिए कांग्रेस शासित सरकारों को बचाने के लिए रणनीति बनाने में कांग्रेस नेतृत्व जुटा है।

**आर.एन.आई.** 59626/94  
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

**प्रधान संपादक**  
**कांति कुमार**

**संपादक**  
**पुष्पा कांति कुमार**

**समाचार संपादक**  
**आनंद कांति कुमार**

कानूनी सलाहकार:  
वी के अरोड़ा, एडवोकेट  
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।  
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**आवश्यकता है आवश्यकता है एक माली की।**

**संपर्क करें-**  
**9358134808**